# 14 महीने में ही बदहाल हो गया दो करोड़ से बना कोकर का डिस्टिलरी पार्क

- 29 जनवरी 2018 को हुआ था इस पार्क का उदघाटन
- मेन गेट दिखावा बना ग्रिल काट कर पार्क में घुस रहे हैं लोग

संवाददाता ▸ रांची

रांची नगर निगम ने करीब 14 महीने पहले कोकर डिस्टिलरी पुल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क का निर्माण कराया था. पार्क के निर्माण कराने में करीब दो करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. मौजूदा समय में इस पार्क की हालत खस्ता हो चुकी है. पार्क में चारों ओर झाड़ियां उग आयी हैं. पाथ वे के ऊपर में नाली पानी बह रहा है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है. पार्क की सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर तार से घेराबंदी की गयी थी. लेकिन असामाजिक तत्वों ने तार को ही काट दिया गया है. बाहर से आनेवाले लोग प्रवेश शुल्क से बचने के लिए अब इसी रास्ते से पार्क में प्रवेश करते हैं. इससे पार्क का ठेका लेनेवाले संवेदक को भी नुकसान हो रहा है. शौचालयों पर लगा रहता है तालास्वच्छ भारत मिशन के तहत रांची नगर निगम शहरवासियों को खुले में शौच करने से रोक रहा है. लेकिन, निगम के इस पार्क में ही स्वच्छ भारत मिशन का मखौल उड़ाया जा रहा है. पार्क में महिला और पुरुष के लिए शौचालय तो बनाये गये हैं. लेकिन, अधिकतर समय इन शौचालयों में ताला ही बंद रहता है. इससे पार्क में आनेवाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.

> मुझे पार्क की स्थिति की जानकारी है. अभी आचार संहिता लगी हुई है. आचार संहिता के समाप्त होने के बाद अभियंताओं के टीम के साथ पार्क का निरीक्षण किया जायेगा. इस दौरान जो भी खामियां मिलेंगी उन्हें प्राथमिकता से सुधारा जायेगा.
>
> **संजीव विजयवर्गीय,** डिप्टी मेयर

कोकर डिस्टिलरी पुल के समीप स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क के अंदर उग आयी हैं झाड़ियां और टूटी घेराबंदी को पार कर अंदर जाता युवक.

## को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पर केस

**धनबाद.** धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश चौधरी व एमडी एजी कुजूर के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है. बैंक एमडी व चेयरमैन पर चुनाव आचार संहिता के दौरान एकमुश्त ऋण समझौता योजना को लागू करने का आरोप है. मामले में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ए दोड्डे ने शुक्रवार को को-ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सुरेश चौधरी के खिलाफ एफआइआर करने व एमडी एजी कुजूर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही, बैंक की एकमुश्त ऋण समझौता योजना को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है. मालूम हो कि बैंक का लगभग 25 करोड़ रुपये एनपीए है. चार हजार लोगों ने बैंक से लोन लिया और चुकता नहीं किया. बैंक की ओर से नोटिस पर नोटिस दिया गया, लेकिन एनपीए की स्थिति में सुधार नहीं हुआ. 2006 से बैंक सुपरशीड था. पिछले साल चुनाव हुआ और 21 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया. बोर्ड के गठन के बाद ऋण योजनाओं में काफी तब्दील की गयी.

## . नहीं हो सका बीज खरीद का टेंडर, विभाग ने कमेटी के पास भेजा

# राज्य में चुनाव आचार संहिता में फंसी खरीफ की योजना

मनोज सिंह ▸ रांची

राज्य में खरीफ मौसम में चलायी जाने वाली योजना चुनाव आचार संहिता में फंस गयी है. आचार संहिता के कारण किसानों को बीज व अन्य उपकरण मिलने में देरी होगी. मई माह के अंत से किसानों के बीच बीज और अन्य उपकरणों का वितरण शुरू हो जाता है. टेंडर व अन्य वितरण स्कीम में चुनाव आचार संहिता के कारण रोक है. राज्य में सबसे अधिक खेती खरीफ के मौसम में ही होती है. इसमें धान व अन्य खाद्यान्न सामग्री लगायी जाती है. राज्य में सबसे अधिक किसान धान की खेती ही करते हैं. विभाग ने बीज व अन्य उपकरणों की जरूरत के हिसाब से स्कीम तैयार कर लिया है. स्कीम राज्य से स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा गया है. स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमोदन मिलने के बाद यह चुनाव आयोग जायेगा. चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही टेंडर हो पायेगा.

### शॉर्ट टेंडर कर सकता है विभाग

कृषि विभाग चुनाव आचार संहिता को देखते हुए बीज वितरण के लिए शॉर्ट टेंडर की तैयारी कर रहा है. विभागीय अधिकारियों का मानना है कि अगर चुनाव के बीच में निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली तो शार्ट टेंडर किया जायेगा. शार्ट टेंडर के बाद आपूर्तिकर्ताओं से समय से बीज उपलब्ध कराने का आग्रह होगा. कंपनियों को टेंडर के बाद आपूर्ति आदेश दिया जाता है. आपूर्ति आदेश मिलने के बाद कंपनियां एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक संबंधित जिलों में बीज पहुंचाने में समय लगाती हैं.

### 15 जून के बाद शुरू हो जाती है खेती

खरीफ की खेती राज्य में 15 जून के बाद शुरू हो जाती है. राज्य में मॉनसून आगमन का तय समय 15 जून के आसपास है. बिचड़ा लगाने का समय इसी समय से शुरू हो जाता है.

### सूखा झेल चुके हैं किसान

झारखंड के किसान पिछले खरीफ मौसम में सूखा की मार झेल चुके हैं. राज्य के करीब 129 प्रखंड पूरी तरह सूखाग्रस्त थे. इसमें 93 प्रखंडों में स्थिति ज्यादा खराब थी. इसे देखते हुए भारत सरकार की टीम ने झारखंड का दौरा भी किया था. दौरे के बाद राज्य सरकार ने राहत कार्य चलाने का आदेश दिया था. इसके लिए राज्य के आपदा कोष में पड़े पैसे को खर्च करने की अनुमति राज्य सरकार को दी गयी है.

# मोदी जाति-धर्म को देखे बिना गरीबों का घर रोशन करने में जुटे हैं : नीरा

- शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने जमशेदपुर में किया भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का प्रचार
- प्रेस वार्ता में कहा : सरकार ने स्कूल बंद नहीं किया, शिक्षा का माहौल और बेहतर बनाया

प्रमुख संवाददाता ▸ रांची/जमशेदपुर

पत्रकारों को संबोधित करतीं शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव व अन्य.

शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वह सूर्य हैं, जो जाति-धर्म देखे बिना गरीबों का घर रोशन कर रहे हैं. इस सरकार के कारण गरीबों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है. उन्होंने सरकार ने बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई का ख्याल रखा है. मंत्री ने दावा किया कि जमशेदपुर संसदीय सीट पर भाजपा डेढ़ लाख से अधिक वोटों से जीतेगी और सूबे में सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा.

चुनाव प्रचार अभियान के दौरान साकची स्थित एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नीरा यादव ने कहा कि महागठबंधन का न तो नेता तय है और न ही एजेंडा. ऐसे में उनके हाथों में देश की बागडोर जनता कतई नहीं सौंप सकती. एनडीए प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में नीरा यादव ने दो दिनों तक चुनाव प्रचार किया. स्कूल विलय पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्ष स्कूल विलय के मामले को दुष्प्रचारित किया. राज्य सरकार ने भवनों को स्कूल के रूप में विकसित किया. उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में रहते झामुमो ने केवल भवन निर्माण किया था और इसमें कमीशन का खेल चलता रहा. भाजपा सरकार के आते ही झामुमो और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की कमीशनखोरी बंद हो गयी. सरकार ने किसी स्कूल को बंद नहीं कराया. बल्कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने के लिए नजदीक के स्कूलों में समायोजित किया गया. संवाददाता सम्मेलन मे भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, कुलवंत सिंह बंटी और मीडिया प्रवक्ता अंकित आनंद मौजूद थे.

# 2500 करोड़ की योजनाओं पर जल्द शुरू होगा काम

विशेष संवाददाता ▸ रांची

- आचार संहिता समाप्त होते ही शुरू होगा 600 सड़क योजनाओं का काम
- बड़ी संख्या में योजनाओं के टेंडर का हो चुका निष्पादन, कई का टेंडर बाकी

आचार संहिता समाप्त होते ही करीब 2500 करोड़ की सड़क निर्माण योजनाओं पर काम शुरू हो जायेगा. इसके तहत करीब 600 सड़कों का निर्माण किया जाना है. इनमें ज्यादातर ग्रामीण सड़कें हैं. अधिकतर योजनाओं का टेंडर हो गया है. आचार संहिता के बाद केवल टेंडर निष्पादन करना है.

वहीं, बड़ी संख्या में ऐसी योजनाएं हैं, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गयी है, लेकिन आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं किया जा सकता था. अब उन पर टेंडर किया जायेगा. इस तरह सारी योजनाओं पर एक साथ जून-जुलाई में काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है. मुख्य सचिव के निर्देश के बाद संबंधित विभाग और सक्रिय हो गये हैं. मुख्य सचिव ने कहा है कि आचार संहिता समाप्त होते ही काम शुरू करा दिया जाये. इसके पहले की सारी प्रक्रियाएं कर ली जायें, जो आचार संहिता के कारण प्रभावित नहीं होते हैं.

इन पर शुरू होगा काम

जानकारी के मुताबिक ज्यादातर काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है. योजना के तहत करीब 300 सड़क योजनाओं का टेंडर हो गया है. इन पर टेंडर पड़ा हुआ है. केवल इसका निष्पादन करना है. वहीं करीब 150 योजनाएं स्वीकृति है. इन पर टेंडर करना है. इस तरह पीएमजीएसवाइ के 450 योजनाओं का काम शुरू होगा.

इस तरह करीब 600 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू कराना है. ग्रामीण कार्य विभाग के करीब 100 योजनाओं पर काम शुरू कराना है. टेंडर हो गया था, लेकिन आचार संहिता के कारण निष्पादन नहीं हो सका. ऐसे में अब आचार संहिता समाप्ति के बाद इनका निष्पादन होगा. ये योजनाएं करीब 200 करोड़ की हैं. पथ निर्माण विभाग की भी करीब 35-40 योजनाओं पर काम शुरू कराने की तैयारी की गयी है. पथ विभाग करीब 1600 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू कराने जा रहा है. यानी इतनी लागत की सड़कें बनायी जायेंगी. फिलहाल इतनी योजनाओं पर काम शुरू होगा. हालांकि इस वित्तीय वर्ष में योजनाओं की और संख्या बढ़ायी जा सकती है.

# आधार में सुधार के लिए उमड़ रही भीड़

- डाकघर में सुधार के लिए 80 हजार आवेदन, कम पड़ रही मशीन

वरीय संवाददाता ▸ रांची

आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए लोगों की बढ़ती तादाद यूआइडीएआइ के लिए परेशानी बनती जा रही है. रोजाना एक आधार सेवा केंद्र में आधार नंबर एनरोलमेंट से ज्यादा आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लोग आ रहे हैं. कार्ड में नाम, पता और उम्र में संशोधन कराने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड बनाने से ज्यादा इसमें संशोधन के लिए भीड़ जुट रही है. अकेले डाकघर के आधार केंद्रों पर बड़ी संख्या में आधार अपडेट का काम किया जा रहा है. दूसरी तरफ, केंद्रों पर मशीनों की संख्या कम होने और भीड़ ज्यादा होने के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं इस काम में लगे कर्मियों को भी परेशानी हो रही है. जीपीओ में बने सेंटर पर सुधार के लिए पहुंचे एक दंपती ने कहा कि वह किराये के मकान में रहते हैं. हर छह महीने-साल भर में उनका पता बदल जाता है, ऐसे में सुधार कराना उनकी मजबूरी है. आपको बता दें कि इसके पहले शहर के करीब 250 से ज्यादा ऑनलाइन कियोस्क सेंटरों पर आधार का काम किया जा रहा था, लेकिन यूआइडीएआइ ने कियोस्क सेंटरों पर आधार का काम बंद कर दिया है, जिसके बाद अब सरकारी दफ्तरों में आधार एनरोलमेंट काम किया जा रहा है.

आधार कार्ड में सुधार के लिए पहुंचे लोग.

### डाकघर में तीन महीने में 80 हजार से ज्यादा आवेदन

विभिन्न डाकघरों में कार्यरत 207 सेंटरों पर आधार कार्ड बनाने व इसमें सुधार का काम किया जा रहा है. मार्च तक के डेटा के हिसाब से इनमें जहां मात्र 9,330 नये आधार कार्ड बनाये गये, वहीं इस दौरान आधार कार्ड में सुधार के लिए 80,619 आवेदन दिये गये.

### दूसरी बार जन्मदिन अपडेट करना मुश्किल

अपवाद की स्थिति में ही आधार में दर्ज जन्म तिथि को एक से ज्यादा बार अपडेट किया जा रहा है. कार्ड धारक को यूआइडी के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने के बाद ही इसमें बदलाव संभव है. यह काम एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के जरिये होगा.

### सुधार कराने के लिए चुकाने पड़ रहे शुल्क

यूआइडीएआइ की ओर से अब नया आधार कार्ड बनवाने या फिर उसमें बदलाव करवाने के लिए लोगों को 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं. आधार बनवाने, अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट ही फ्री में हो रहे हैं. अन्य बायोमीट्रिक अपडेट, नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल में सुधार के लिए 50 रुपये, रंगीन प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये जबकि ब्लैक एंड व्हाइट के लिए 10 रुपये चार्ज किये जा रहे हैं.

# देवघर में मालवाहक वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत

- दुमका आइजी को मिली शिकायत, जांच के लिए आइजी ने पुलिस अफसर को दिया

वरीय संवाददाता ▸ रांची

एक एएसआइ और एक बड़े पुलिस अफसर के कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी के साथ गौतम नामक व्यक्ति मालवाहक वाहनों की पासिंग का काम देवघर में करवाता है. पासिंग के दौरान हाइवा और ट्रक पर लदे ओवर लोडेड सामग्री के बदले मोटी रकम वसूल करता है. सूत्र बताते हैं कि पाकुड़ और दुमका की ओर से आनेवाले गिट्टी लदे वाहनों से वसूली की जाती है. पूर्व में उक्त एएसआइ निलंबित भी किया गया था. लेकिन निलंबन मुक्त होने के बाद फिर से वसूली के धंधे में शामिल हो गया है. इस मामले में देवघर के बैधनाथपुर निवासी अमोद कुमार नामक व्यक्ति ने दुमका प्रक्षेत्र के आइजी सह सीआइडी आइजी से इसकी शिकायत की है. साथ ही इसकी प्रतिलिपि एंटी करप्शन ब्यूरो को भी भेजी है.

**इन नंबर के वाहनों से अवैध वसूली का आरोप** : शिकायत करनेवाले ने कुल 46 वाहनों की सूची आइजी को भेजी है. इनमें जेएच-12सी-8306, बीआर-01जीइ-5177, बीआर-21जीबी-8981, बीआर-21जीए-2785, बीआर-21जीए-8981, बीआर-01जीएफ-8921, जेएच-04एच-9688, जेएच-04एच-7527, बीआर-10जी-7751, जेएच-15टी-5777, जेएच-15टी-9287, जेएच-15एल-1575, बीआर-52जी-1321, बीआर-52जी-2584, बीआर-52जी-4280, बीआर-52जी-1406, बीआर-52जी-1763, बीआर-52जी-2503, बीआर-52जी-3071, बीआर-27जी-2307, बीआर-01जीडी-3553, बीआर-52जी-2959, बीआर-21जीबी-2009 सहित अन्य शामिल हैं.

# ठेकेदारों ने पीएमजीएसवाइ की ओर किया अपना रुख

वरीय संवाददाता ▸ रांची

राज्य के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर अपना रुख किया है. यानी वे अब पीएमजीएसवाइ के कार्यों में टेंडर भरने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इतना ही नहीं पीएमजीएसवाइ के काम से परहेज करनेवाले ठेकेदार भी अब वहां टेंडर भर रहे हैं. खासकर पथ निर्माण विभाग का काम लेनेवाले ठेकेदार इस ओर जा रहे हैं.

इस पर ठेकेदारों का कहना है कि पीएमजीएसवाइ का भुगतान बेहतर है. ठेकेदारों का पैसा नहीं फंस रहा है. विपत्र के विरुद्ध तत्काल भुगतान होता है. इस वजह से वहां काम करना आसान हो रहा है. वहीं पथ निर्माण विभाग में स्थिति इसके उलट हो गयी है. वहां भुगतान की स्थिति महीनों से खराब है. ऐसे में ठेकेदार फंसे रह जा रहे हैं. आर्थिक संकट से उन्हें जूझना पड़ रहा है.

### रेट में हुआ है संशोधन

गौरतलब है कि हाल के दिनों में पीएमजीएसवाइ के रेट में भी संशोधन हुआ है. पहले इसका रेट काफी कम था, लेकिन कुछ माह पहले नक्सल इलाकों के लिए स्वीकृत बड़ी योजनाओं का इस्टीमेट भी बेहतर कर दिया गया है. संशोधित इस्टीमेट पर ठेकेदारों को काम करना आसान हो रहा है. वहीं पीएमजीएसवाइ से 10 से 15 करोड़ रुपये की योजनाएं भी स्वीकृत की गयी थीं. ठेकेदार मानते हैं कि इसके काम में ज्यादा लाभ नहीं है. साथ ही सुदूर इलाकों में ही काम हैं, फिर भी यहां काम करने से पेमेंट नहीं लटक रहा है. ऐसे में ठेकेदारों को बड़ी राहत मिल रही है.

### काम के लिए मुश्किल से मिल रहे थे ठेकेदार

मालूम हो कि पीएमजीएसवाइ के काम में काफी मुश्किल से ठेकेदार मिल रहे थे. कई योजनाओं में सिंगल टेंडर पड़ रहे थे. दोबारा टेंडर करने के बाद भी सिंगल टेंडर पड़ रहे थे. ऐसे में सिंगल टेंडर में ही इसका निष्पादन करना पड़ रहा था. योजनाओं में काफी कम ठेकेदारों के भाग लेने पर रेट में कंपीटिशन नहीं हो पा रहा है.

### चतरा में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि

**रांची.** लोकसभा के चुनाव में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत की वृद्धि चतरा संसदीय क्षेत्र में हुई है. यहां करीब 10.52 फीसदी की वृद्धि हुई है. सबसे कम वृद्धि 0.73 फीसदी रांची संसदीय क्षेत्र में हुई है. हजारीबाग में करीब 1.15 फीसदी की वृद्धि हुई है.

| | |
|---|---|
| चतरा | 10.52 |
| लोहरदगा | 8.03 |
| पलामू | 4.94 |
| कोडरमा | 4.17 |
| खूंटी | 2.84 |
| हजारीबाग | 1.15 |
| रांची | 0.73 |

# धनबाद में प्रचार खत्म, अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू

- बूथ मैनेजमेंट में जुटे प्रत्याशी, 2539 बूथों पर 20.48 लाख मतदाता कल डालेंगे वोट

विशेष संवाददाता ▸ धनबाद.

धनबाद लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार को समाप्त हो गया. शाम पांच बजे के बाद यहां डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है. साथ ही अधिकांश प्रत्याशी बूथ मैनेजमेंट में जुट गये हैं. 2539 बूथों पर 20.48 लाख मतदाता रविवार को वोट डालेंगे. चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में धनबाद एवं निरसा में बाइक जुलूस निकाल कर रोड शो किया गया. धनबाद शहर के भुईफोड़ मंदिर के समीप बाइक जुलूस सह रोड शो का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं सांसद सह भाजपा प्रत्याशी पीएन सिंह ने किया. श्री मुंडा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अबकी बार पांच लाख पार के नारे को चरितार्थ करें. विरोधियों की जमानत जब्त करा दें. थोड़ी दूर तक चल कर श्री मुंडा झालदा निकल गये. सांसद श्री सिंह भी निरसा निकल गये. इसके बाद धनबाद विधायक के नेतृत्व में बाइक जुलूस रणधीर वर्मा चौक, कंबाइंड बिल्डिंग, पूजा टॉकीज, बैंक मोड़, करकेंद, पुटकी होते हुए मुनीडीह पहुंच कर समाप्त हुआ. जुलूस में भाजपा नेता नितिन भट्ट, मनोज मालाकार, ललन मिश्र, राजकुमार मंडल, दिलीप सिंह, निर्मल प्रधान, मनोज गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समर्थक शामिल थे.

### महागठबंधन के पक्ष में पहुंचे बाबूलाल मरांडी

महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद के समर्थन में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनबाद पहुंचे. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. साथ ही लोगों से महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की. कांग्रेस प्रत्याशी व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जगह-जगह जनसंपर्क अभियान चलाया. पार्टी का पूरा फोकस बूथ मैनेजेंट पर लगा है. देर रात तक बूथ कमेटियों के साथ बैठकों का दौर चलता रहा.

### मतदान के लिए प्रशासन तैयार

12 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है. डीसी ए दोड्डे के अनुसार तीन स्थानों से शनिवार को पोलिंग पार्टी डिस्पैच की जायेगी. यहां छह सुपर जोनल दंडाधिकारी व 20 जोनल दंडाधिकारी बनाये गये हैं. सुरक्षा के लिए हर बूथ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है. 30 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स भी मंगाया गया है.

**सावधानी** ● झारखंड के चार लोकसभा क्षेत्र चाईबासा, गिरिडीह, धनबाद व जमशेदपुर में मतदान कल

# चाईबासा व गिरिडीह में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौती

वरीय संवाददाता ▸ रांची

- चाईबासा में इनामी मिसिर बेसरा, किशन दा व अनल दा जैसे कई खूंखार नक्सली
- गिरिडीह में नुनूचंद महतो, प्रशांत मांझी और बच्चन दा का दस्ता एक्टिव
- धनबाद में नुनूचंद महतो और जमशेदपुर में आकाश मंडल व सचिन दस्ता

लोकसभा के सातवें और झारखंड में तीसरे चरण में चार लोकसभा क्षेत्रों चाईबासा, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में 12 मई को मतदान होना है. चारों लोकसभा क्षेत्रों में चाईबासा जिले में एक-दो थाना क्षेत्रों को छोड़ दिया जाये, तो अधिकांश थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं. इनमें सोनुआ, गोइलकेरा, गुदरी, बड़गांव, किरीबुरू, जरायकेला, छोटा नागरा, मनोहरपुर, चिड़िया माइंस ओपी व टोंटो आदि थाना क्षेत्र अति नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों की श्रेणी में आता है. इसी तरह गिरिडीह में पारसनाथ, उतरी डुमरी, निमियाघाट, पीरटांड़, कुकरा व मधुबन थाना क्षेत्र में भी नक्सलियों का ज्यादा प्रभाव माना जाता है.

वहीं, धनबाद में हरिहरपुर, राजगंज, तोपचांची, बनियाडीह, टुंडी, पूर्वी टुंडी व बरबड्डा नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं. जबकि जमशेदपुर में गुड़ाबांध समेत एक दो और थाना क्षेत्र नक्सलियों के आंशिक प्रभाव वाला माना जाता है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक चाईबासा जिले में फिलवक्त माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य और एक करोड़ के इनामी किशन दा, मिसिर बेसरा, अनल दा के अलावा सुरेश मुंडा और जीवन कंडुलना का दस्ता मौजूद है. गिरिडीह की बात करें तो यहां पर नुनूचंद महतो, प्रशांत मांझी और बच्चन दा का दस्ता एक्टिव है. इसके पड़ोसी जिले धनबाद में भी नुनूचंद महतो दस्ता का प्रभाव माना जाता है. इसी तरह चाईबासा और सरायकेला जिले की सीमा पर हार्डकोर नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग दा अपने दस्ते के साथ बताया जाता है. ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना पुलिस प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण है. खासकर चाईबासा और गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्र में. वर्तमान में चाईबासा और गिरिडीह ही दो जिले ऐसे हैं, जहां पर प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों का प्रभाव ज्यादा माना जाता है. ऐसे में सुरक्षाबलों को सतर्कता से विशेष रणनीति के तहत चुनाव के दौरान आने-जाने में सावधानी बरतनी होगी. हालांकि इससे पूर्व 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उक्त चारों लोकसभा क्षेत्रों से किसी तरह की बड़ी वारदात नक्सलियों द्वारा किये जाने की खबर सामने नहीं आयी थी. अब तक पुलिस प्रशासन ने दो चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सफलता पायी है. लिहाजा माना जाना चाहिए कि तीसरा चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण संपन्न होगा.

### सीएम ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

**जामताड़ा.** सीएम रघुवर दास ने शुक्रवार को जामताड़ा की धरती से संताल परगना के चुनाव प्रचार के लिए शंखनाद कर दिया है. शुक्रवार को साढ़े चार बजे सीएम रघुवर दास हेलीकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. उसके बाद सुभाष चौक स्थित एकता श्री होटल में सीएम पहुंच कर नाला, जामताड़ा एवं सारठ विधानसभा के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर कार्यकर्ताओं को सीएम ने चुनावी मंत्र दिया. सीएम रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिये. कोर कमेटी की बैठक के दौरान सीएम ने बारी-बारी से तीनों विधानसभा के कोर कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बनायी. कोर कमेटी के बैठक के उपरांत सीएम ने एसटी मोर्चा एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.